



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032020-218810  
CG-DL-E-19032020-218810

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1047]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2020/फाल्गुन 29, 1941

No. 1047]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2020/PHALGUNA 29, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2019

**का.आ. 1165(अ).**—केंद्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 26क, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 26क और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 22ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित न्यायालयों पर अधिकारिता रखने वाले माननीय उच्च न्यायालयों के संबंधित मुख्य न्यायमूर्तियों की सहमति प्राप्त करने के पश्चात्, उसके स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा उल्लिखित संबंधित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियमों के अधीन उक्त न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	विद्यमान न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, शिलांग	मेघालय राज्य
2.	अपर जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, पोर्ट ब्लेयर, अंदमान और निकोबार द्वीप	अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र

[फा. सं. 10/49/2017-भाग]

आनंद मोहन बजाज, संयुक्त सचिव (वित्तीय बाजार)

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th March, 2020

**S.O. 1165(E).**—In exercise of the powers conferred by section 26A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), section 26A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and section 22C of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Central Government, after obtaining the concurrence of the respective Chief Justices of the Hon'ble High Courts having jurisdiction over the courts mentioned in column (2) in the Table below, hereby designates the said courts as Special Courts under the aforesaid Acts to exercise jurisdiction in the respective State and Union territory, as mentioned in corresponding entry in column (3) thereof, namely:-

**TABLE**

<b>Sl. No.</b>	<b>Existing court</b>	<b>Jurisdiction as Special Court</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Court of District and Sessions Judge, Shillong	State of Meghalaya
2.	Court of Additional District and Session Judge, Port Blair, Andaman and Nicobar Islands	Union territory of Andaman and Nicobar Islands

[F. No.10/49/2017-PM]

ANAND MOHAN BAJAJ, Jt. Secy. (Financial Markets)